भारत की शैक्षिक व्यवस्था पर दलीय प्रणाली की भूमिका

रजनी वर्मा[1], डॉ. अनामिका रावत[2]

[1]शोधार्थी, राजनीतिक शास्त्र, भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल.
[2]गाइड, राजनीतिक शास्त्र, भाभा विश्वविद्यालय, भोपाल.

OPEN ACCESS

Volume: 3

Issue: 2

Month: June

Year: 2024

ISSN: 2583-7117

Published: 14.06.2024

Citation:

रजनी वर्मा**1,** डॉ. अनामिका रावत**2,** "भारत की शैक्षिक व्यवस्था पर दलीय प्रणाली की भूमिका" International Journal of Innovations In Science Engineering And Management, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 67–74.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

सारांश

यह समीक्षा पत्र भारत में दलीय प्रणाली और शैक्षिक प्रणाली के बीच के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है, और यह पता लगाता है कि राजनीतिक गतिशीलता शैक्षिक नीतियों, प्रथाओं और परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। मौजूदा साहित्य और केस अध्ययनों के व्यापक विश्लेषण के माध्यम से, काग़ज़ी शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक अवसरों में समानता और समग्र शैक्षिक विकास पर विभिन्न दलीय प्रणालियों, राजनीतिक विचारधाराओं और शासन संरचनाओं के प्रभाव की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, काग़ज़ी शिक्षा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में राजनीतिक दलों की भूमिका की जांच करता है, और शैक्षिक क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप, ध्रुवीकरण और विखंडन की चुनौतियों, अवसरों और निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। राजनीति और शिक्षा के बीच जटिल अंतरसंबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करके, यह काग़ज़ी भारत में शैक्षिक प्रणाली को आकार देने वाले कारकों की गहरी समझ में योगदान देता है और एक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रदान करता है जो सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा करती है।

सूचक शब्द: दलीय प्रणाली, भारत, शिक्षा नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप, ध्रुवीकरण, विखंडन, शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता, समानता, शासन।

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा प्रणाली देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है, अपने नागरिकों के भविष्य को आकार देती है और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देती है।

भारतीय शैक्षिक परिदृश्य के अवलोकन से एक विविध और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का पता चलता है जिसमें स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तर, उच्च शिक्षा संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान संगठन शामिल हैं। इस प्रणाली की विशेषता सार्वजनिक और निजी संस्थानों का मिश्रण है, जो एक विशाल और विषम आबादी की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करती है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली और दलीय प्रणाली के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। भारत में राजनीतिक दल शिक्षा नीति, वित्त पोषण आवंटन और शासन संरचनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर सत्ता में रहने वाली दलीय अक्सर ऐसी शिक्षा नीतियां बनाती है जो उसके वैचारिक रुख, प्राथमिकताओं और चुनावी वादों को प्रतिबिंबित करती हैं। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल शिक्षा मंत्रियों और विश्वविद्यालय प्रशासकों जैसे प्रमुख शैक्षिक अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित करते हैं, जिससे शिक्षा क्षेत्र के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। [1]

दलीय प्रणाली की गतिशीलता शैक्षिक सुधारों और पहलों को भी प्रभावित करती है। राजनीतिक सत्ता में बदलाव, गठबंधन निर्माण और वैचारिक परिवर्तन से शिक्षा नीतियों, पाठ्यक्रम संशोधन और अनुदान आवंटन में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसके अलावा, भाषा नीति, पाठ्यपुस्तक सामग्री और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे शिक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण अक्सर एक विवादास्पद मुद्दा बन जाता है, जिसमें राजनीतिक दल अपने चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों और मतदाता जनसांख्यिकी के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं।

1.1. शिक्षा नीति पर दलीय राजनीति का प्रभाव

भारत में शिक्षा नीति पर दलीय राजनीति का प्रभाव गहरा और दूरगामी है, जो शैक्षिक पहलों के निर्माण, कार्यान्वयन और परिणामों को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल, अपनी विचारधाराओं, चुनावी वादों और शासन रणनीतियों के माध्यम से, शिक्षा नीति की दिशा और प्राथमिकताओं को महत्वपूर्ण रूप से आकार देते हैं। कई प्रमुख पहलू शिक्षा नीति पर दलगत राजनीति के प्रभाव को उजागर करते हैं: [2]

1. **नीति निर्माण:** भारत में शिक्षा नीतियां अक्सर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल या गठबंधन की विचारधाराओं और कार्यावली को प्रतिबिंबित करती हैं। दलें अपने चुनावी वादों और वैचारिक झुकाव के आधार पर शिक्षा के कुछ पहलुओं, जैसे पहुंच, गुणवत्ता या समानता को प्राथमिकता दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, समाजवादी रुझान वाली दलीय शिक्षा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की वकालत कर सकती हैं, जबकि नवउदारवादी रुख वाली दलीय निजीकरण और बाजार-संचालित सुधारों पर जोर दे सकती हैं।

2. **धन आवंटन:** शिक्षा के लिए धन का आवंटन दलीय राजनीति से प्रभावित एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन सरकारी प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसे अक्सर राजनीतिक विचारों द्वारा आकार दिया जाता है। दलें प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों से समर्थन जुटाने या गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों या क्षेत्रों के लिए संसाधन आवंटित कर सकती हैं।

3. **पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र:** राजनीतिक विचारधाराएँ और सांस्कृतिक कार्यावली स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम विकास और शैक्षणिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। पार्टियाँ शैक्षिक पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ मूल्यों, विश्वासों या आख्यानों को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकती हैं, जिससे इतिहास, भाषा या धार्मिक अध्ययन जैसे कुछ विषयों को शामिल करने या बाहर करने पर बहस हो सकती है।

4. **सकारात्मक कार्रवाई और सामाजिक नीतियां:** भारत में शिक्षा नीतियों में अक्सर सामाजिक न्याय, समानता और सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपाय शामिल होते हैं। राजनीतिक दल इन नीतियों को तैयार करने और लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जिसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण कोटा, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष प्रावधान शामिल हो सकते हैं।

5. **नियामक ढांचा:** राजनीतिक दल कानून, नीति निर्धारण निकायों और प्रशासनिक नियुक्तियों के माध्यम से शिक्षा को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को प्रभावित करते हैं। दलें अपने नीतिगत उद्देश्यों और राजनीतिक कार्यावली के साथ तालमेल बिठाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जैसे नियामक निकायों में सुधार या पुनर्गठन की मांग कर सकती हैं।

कुल मिलाकर, भारत में शिक्षा नीति पर दलीय राजनीति का प्रभाव शैक्षणिक समानता, गुणवत्ता और सामाजिक गतिशीलता के व्यापक लक्ष्यों के साथ राजनीतिक विचारों को संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करता है। जबकि राजनीतिक दल शिक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नीतियां साक्ष्य-आधारित, समावेशी और शिक्षार्थियों और समुदायों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हों।

1.2. शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप

शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप भारत में शिक्षा प्रणाली की अखंडता और प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यह हस्तक्षेप, जो राजनीतिक अभिनेताओं या दलों के अनुचित प्रभाव की विशेषता है, विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है, जिसमें प्रशासनिक नियुक्तियाँ, पाठ्यक्रम परिवर्तन, छात्र राजनीति, कोश पूर्वाग्रह और शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए खतरे शामिल हैं। इस तरह के हस्तक्षेप से अक्सर प्रशासनिक नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के आरोप लगते हैं, जबकि पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यपुस्तक सामग्री में राजनीतिक रूप से प्रेरित परिवर्तन अकादमिक अखंडता से समझौता करते हैं। इसके अलावा, छात्र संघों और परिसर की राजनीति का राजनीतिकरण छात्र प्रतिनिधित्व और वकालत के प्रयासों को कमजोर करता है। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक संबद्धता के आधार पर धन आवंटन और संसाधन वितरण में तरजीही व्यवहार शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और समता को कमजोर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक हस्तक्षेप अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता को खतरे में डालता है, आलोचनात्मक सोच और विद्वतापूर्ण जांच को रोकता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए

शैक्षणिक संस्थानों को अनुचित राजनीतिक प्रभाव से बचाने और शिक्षा की अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता, योग्यता और संस्थागत स्वायत्तता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। [3]

1.3. शिक्षा नीति का ध्रुवीकरण और विखंडन

शिक्षा नीति का ध्रुवीकरण और विखंडन भारत में शिक्षा प्रणाली की सुसंगतता और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। ध्रुवीकरण का तात्पर्य राजनीतिक दलों, शैक्षणिक संस्थानों, नीति निर्माताओं और समुदायों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच दृष्टिकोण और हितों के विचलन से है, जिससे शिक्षा से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विवादास्पद बहस और वैचारिक विभाजन होता है। [4]

इस ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप अक्सर गतिरोध पैदा होता है और आम सहमति तक पहुंचने या सामंजस्यपूर्ण शिक्षा नीतियों को लागू करने की क्षमता ख़राब हो जाती है। दूसरी ओर, विखंडन, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न स्तरों पर असमान नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के प्रसार को संदर्भित करता है, जिससे शिक्षा प्रणाली में विसंगतियां, अतिरेक और अक्षमताएं पैदा होती हैं। प्रतिस्पर्धी हितों, विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी के कारण विखंडन पैदा हो सकता है। साथ में, ध्रुवीकरण और विखंडन शिक्षा नीति की सुसंगतता, समानता और प्रभावशीलता को कमजोर करते हैं, जिससे शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और समानता जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में बाधा आती है। इन मुद्दों के समाधान के लिए हितधारकों के बीच संवाद, सहयोग और समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण को बढ़ावा देने और शिक्षा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अधिक सुसंगतता की आवश्यकता है।

1.4. राजनीति शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करती है

राजनीति कई तरीकों से शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं: [5]

1. **अनुदान:** शिक्षा प्रणालियों को अनुदान की आवश्यकता होती है, और राजनेता अक्सर बजट आवंटित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे तय कर सकते हैं कि स्कूलों को कितना पैसा दिया जाए, जिसका असर शिक्षकों और छात्रों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर पड़ सकता है। वे यह भी तय कर सकते हैं कि नए कार्यक्रमों में निवेश करना है या नहीं। जैसे एसटीईएम पहल या विशेष शिक्षा कार्यक्रम, जिनका शिक्षा की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।

2. **पाठ्यक्रम:** राजनेता स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकते हैं। क्या पढ़ाया जाना चाहिए और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए मानक निर्धारित करके। उनका पाठ्यपुस्तकों और अन्य शिक्षण सामग्री की सामग्री पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, वे कुछ विषयों, जैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) पर दूसरों की तुलना में अधिक जोर देने का निर्णय ले सकते हैं।

3. **परीक्षण:** राजनेता स्कूलों में परीक्षण और मूल्यांकन पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। उन्हें स्कूलों को

मानकीकृत परीक्षण संचालित करने और छात्रों की प्रगति को मापने और शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए परिणामों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। वे स्कूल अनुदान या कॉलेज प्रवेश जैसे कार्यक्रमों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए परीक्षण अंक का भी उपयोग कर सकते हैं।

4. **स्कूल का चयन:** राजनेता चार्टर स्कूल या वाउचर कार्यक्रम जैसी स्कूल चयन नीतियों को बढ़ावा देकर शिक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। ये नीतियां माता-पिता को यह चुनने की अनुमति देती हैं कि उनके बच्चे स्कूल कहाँ जाएँ। जिससे स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और संभावित रूप से समग्र शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

5. **शिक्षक वेतन और मूल्यांकन:** राजनेता शिक्षकों के वेतन और उन मानदंडों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिनके द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। वे योग्यता-आधारित वेतन की वकालत कर सकते हैं या यह मांग कर सकते हैं कि शिक्षक कुछ मानकों को पूरा करें। जैसे कि वेतन वृद्धि प्राप्त करने या अपना रोजगार बनाए रखने के लिए व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करना।

साहित्य समीक्षा

शिक्षा और राजनीति का एक दूसरे से सहजीवी संबंध है। हालाँकि, जब कोई दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, तो नकारात्मकताएँ आ जाती हैं। यह निबंध कई शोध लेखों के आधार पर इस रिश्ते की पड़ताल करता है और राय देता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के मामले में; ऐसी नीतियां बनाना महत्वपूर्ण है जो भारतीय जनता दलीय, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीतिक गुट है, की हिंदू केंद्रीय विचारधाराओं के कारण उत्पन्न हुई नकारात्मकताओं को खत्म करने में मदद करेगी। [6]

लेखकों ने यह अध्ययन तीन मुख्य गतिविधियों के माध्यम से किया। सबसे पहले, उन्होंने 76 देशों में शिक्षा सुधार और सीखने के रुझानों को शामिल करते हुए एक डेटाबेस स्थापित किया। इस डेटाबेस का उपयोग करते हुए, उन्होंने सुधार के प्रकारों और सीखने के परिणामों के रुझान के बीच संबंध का विश्लेषण किया। दूसरे, उन्होंने जांच की कि राजनीतिक और आर्थिक कारकों के साथ-साथ शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं ने सीखने में निरंतर सुधार या गिरावट को कैसे प्रभावित किया। तीसरा, उन्होंने शिक्षा गुणवत्ता सुधारों के राजनीतिक पहलुओं से संबंधित विभिन्न विषयों को उजागर करने के लिए नौ देशों पर केस अध्ययन किया। निष्कर्षों के संश्लेषण ने सूचना परिनियोजन, गठबंधन कार्य और रणनीतिक परिवर्तन निर्माण में रुझानों की पहचान की। हालाँकि डेटाबेस के निष्कर्षों ने आम तौर पर सीखने से जुड़े आर्थिक और राजनीतिक संकेतकों के साथ मजबूत संबंध स्थापित नहीं किए, लेकिन उन्होंने यह खुलासा किया कि प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा पहुंच में विस्तार लगातार सीखने के रुझानों से जुड़ा नहीं था। हालाँकि, पूर्व-प्राथमिक नामांकन में वृद्धि से निरंतर सीखने में सुधार की अधिक संभावना दिखाई दी। शिक्षा और आर्थिक विकास पर सरकारी खर्च में बदलाव का दीर्घकालिक सीखने के रुझान के साथ गहरा संबंध नहीं था, हालांकि त्वरित विकास ने कुछ संकेतात्मक संबंध दिखाया। दिलचस्प बात यह है कि लोकतंत्र के स्तर में सीखने में सुधार या गिरावट की

IJISEM
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

भविष्यवाणी नहीं की गई है, सबसे महत्वपूर्ण सुधार अक्सर गैर-लोकतांत्रिक देशों में शुरू होते हैं। फिर भी, देशों के भीतर बढ़े हुए लोकतंत्रीकरण ने सीखने में सुधार के साथ कुछ संबंध दिखाया है। [7]

भारत का दलगत राजनीतिक क्षेत्र भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ी संख्या में दलों से भरा पड़ा है। उनमें से कई विशिष्ट क्षेत्रों और राज्यों में स्थित हैं, जो सामाजिक और भाषाई पहचान के आसपास निर्मित हैं। हालाँकि इसने पार्टियों के प्रतिनिधि चरित्र को बढ़ाया, इसने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अस्थिर सरकारों के विभिन्न रूपों में भी योगदान दिया। दो प्रमुख राष्ट्रीय दलें- कांग्रेस और भारतीय जनता दलीय-गठबंधन बनाने के लिए तैयार और इच्छुक हो गईं, जिससे केंद्र और राज्यों दोनों में गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत हुई, जिससे दलों को अपनी शक्ति और भुगतान बढ़ाने में मदद मिली। विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति व्यापक आर्थिक नीति पर एकजुट होने की रही है, लेकिन सामाजिक नीतियों और राष्ट्र निर्माण और धर्मनिरपेक्षता जैसे भारत के सामने आने वाले बड़े मुद्दों पर मतभेद जारी है। आंतरिक लोकतंत्र की निरंतर कमी के साथ-साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार और ग्राहकवादी प्रथाओं का बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। शासन का एक व्यापक दृष्टिकोण, सत्ता को केंद्रित करने और व्यक्तिगत संवर्धन को आगे बढ़ाने के प्रलोभनों का विरोध करने से पार्टियों को बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए नीतियां देने में मदद मिलेगी। [8]

एक समृद्ध सैद्धांतिक साहित्य का तर्क है कि, डुवर्गर के कानून के विपरीत, बहुलता मतदान नियम दो-पक्षीय प्रणाली का निर्माण करने में विफल हो सकता है जब मतदाता चुनावी स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी साझा नहीं करते हैं। हम निर्वाचन क्षेत्र और व्यक्तिगत स्तर के आंकड़ों का उपयोग करके भारत के मामले में इस सूचनात्मक परिकल्पना का अनुभवजन्य संचालन और परीक्षणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। अत्यधिक निरक्षर निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदाताओं के बीच सूचना तक पहुंच और सूचना-साझाकरण कम है, मतदाता अक्सर दो सबसे व्यवहार्य पार्टियों पर समन्वय करने में विफल रहते हैं। अत्यधिक साक्षर निर्वाचन क्षेत्रों में, मतदाता वोट की बर्बादी से बचने में कहीं अधिक सफल होते हैं - सूचनात्मक परिकल्पना के अनुरूप। सूक्ष्म स्तर पर, ये समग्र-स्तरीय रूप व्यक्तिगत जानकारी और सूचनात्मक संदर्भ की परस्पर क्रिया से प्रेरित होते हैं: घने सूचनात्मक वातावरण में, यहां तक कि कम जानकारी वाले मतदाता भी व्यवहार्य दलों की सफलतापूर्वक पहचान कर सकते हैं और उन्हें वोट दे सकते हैं, लेकिन विरल सूचनात्मक वातावरण में, सफल रणनीतिक मतदान के लिए सूचना तक व्यक्तिगत पहुंच आवश्यक है। [9]

यह अध्ययन राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों और लोगों को प्रदान की जाने वाली राजनीतिक शिक्षा की तुलना और तुलना करने के लिए व्यापक क्षेत्रीय अनुसंधान का उपयोग करता है। शोधकर्ता दो राजनीतिक दलों पर ध्यान केंद्रित करता है: डेमोक्रेट दलीय और पुए फाह दीन दलीय, चार महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर: 1) दोनों पार्टियों ने लंबे समय तक थाई राजनीति में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है; 2) दोनों पार्टियों के पास स्पष्ट संगठन और आंतरिक संरचना है; 3) दोनों पार्टियों के पास पिछले वर्षों में दलीय सदस्यों के साथ-साथ दलीय शाखाओं की सटीक संख्या है; और 4) दोनों पार्टियों ने अपने दलीय के

सदस्यों और जनता के लिए कमोबेश राजनीतिक शिक्षा का आयोजन किया है। शोध के परिणाम से पता चलता है कि दलीय गठन के उद्देश्यों, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक भागीदारी और सदस्यों की भर्ती की रणनीति में अंतर के कारण, दोनों पार्टियां अपने सदस्यों और सामान्य रूप से जनता के लिए राजनीतिक शिक्षा संचालित करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का अनुभव करती हैं। [10]

निष्कर्ष

भारत में दलीय प्रणाली की भूमिका शैक्षिक प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है, नीतियों, प्रथाओं और परिणामों को प्रभावित करती है। समीक्षा पत्र राजनीतिक गतिशीलता और शैक्षिक विकास के बीच जटिल संबंध को रेखांकित करता है, शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षिक अवसरों में समानता पर विभिन्न दलीय प्रणालियों, विचारधाराओं और शासन संरचनाओं के प्रभाव को उजागर करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप, ध्रुवीकरण और विखंडन से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, एक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के अवसर हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके और दलीय प्रणाली की ताकत का लाभ उठाकर, भारत अपने शैक्षिक लक्ष्यों को साकार करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर सकता है कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिले।

संदर्भ

[1] J. Hansen, “Political parties,” vol. 13, no. 4, pp. 104-118, 2021, doi: 10.1017/cbo9780511521850.013.

[2] आर. रूपावत, भारत में शिक्षा की राजनीति: नीचे से एक परिप्रेक्ष्य, no. May. 2022.

[3] R. R. Borah, “Impact of politics and concerns with the system,” Int. J. Educ. Plan. Adm., vol. 2, no. 2, pp. 2249-3093, 2020, [Online]. Available: http://www.ripublication.com/ijepa.htm.

[4] एम. एस. भारती, "भारत में दलीय प्रणाली की गतिशीलता: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का एक तुलनात्मक अध्ययन," Przegląd Politol., no. 2, pp. 79-89, 2022, doi: 10.14746/pp.2022.27.2.6.

[5] H. Miwa, “The Transition of Party System in India: From Polarized Pluralism to Moderate Pluralism,” J. Japanese Assoc. South Asian Stud., pp. 96-116, 2006.

[6] ए. पी. दास, "शिक्षा और इसका राजनीतिकरण: भारतीय उदाहरणों के साथ," 2022.

[7] T. P. Williams, “What is the relationship between politics , education reforms , and learning ? Evidence from a new database and nine case studies What is the relationship between politics , education reforms , and learning ? Evidence from a new database and nine case stu,” no. September, pp. 1-140, 2019.

[8] एस. मंडल, "भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका," pp. 1-6, 2018, doi: 10.26480/jmerd.03.2018.01.05.

[9] A. Rozenas and A. Sadanandan, “Literacy, Information, and Party System Fragmentation in India,” Comp. Polit. Stud., vol. 51, no. 5, pp. 555–586, 2018, doi: 10.1177/0010414017710262.

[10] P. Sirivunnabood, “Political Education: The Role of Political Parties in Educating Civil Society on Politics,” Silpakorn Univ. J. Soc. Sci., vol. 16, no. 3, pp. 157–194, 2016.